जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

बीकानेर

Rashtradoot

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 47 संख्याः 281 प्रभात बीकानेर, बुधवार 6 मई, 2026 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रू.

लंदन से न्यूयॉर्क तथा इस्लामाबाद से ढाका तक अखबार भगवा रंग में रंगे से लगे

सभी जगह भारत में हुए विधानसभा चुनाव का विस्तृत कवरेज हुआ, विशेषकर प.बंगाल में भाजपा की जीत का

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 मई। अंतरराष्ट्रीय प्रकाशनों के पन्नों पर भगवा रंग छाया रहा, जब उन्होंने चार राज्यों और एक केन्द्र शासित राज्य में विधानसभा चुनाव के परिणामों की रिपोर्ट दी। अधिकांश विदेशी मीडिया रिपोर्टों में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में चुनावी जीत पर ध्यान केन्द्रित किया गया, जिसने तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी के 15 वर्षों के राज्य पर काबिज शासन को समाप्त कर दिया।

- बीबीसी ने प.बंगाल की जीत को मोदी के बारह साल के शासन की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि बताया। बीबीसी के अनुसार, यह तीन बार मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी की हार ही नहीं, भाजपा की ''इस्टर्न इंडिया'' की यात्रा का गौरवशाली समापन है।
- लंदन के एक और प्रमुख अखबार,''दा गार्जियन'' ने भी प.बंगाल की जीत पर फोकस रखा और इस जीत को विपक्ष का मनोबल तोड़ने और प्रहार के रूप में वर्णित किया।
- न्यूयार्क टाइम्स के लेख के अनुसार, भाजपा की बंगाल की जीत ''ऐतिहासिक'' थी, क्योंकि इसने देश के इस बड़े राज्य में जीत हासिल की है, जहाँ वह पहले कभी भी सरकार बनाने के नज़दीक तक नहीं पहुँची थी।
- वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार, 2024 के आम चुनाव के नतीज़ों ने भाजपा को मजबूर कर दिया था, क्षेत्रीय दलों पर निर्भर होने के लिए। पर, अब मोदी इस जीत के कारण 2029 में चौथी बार प्रधानमंत्री बनने की सोचने लगेंगे।
- पाकिस्तान के डॉन अखबार व ढाका में ट्रिब्युन ने एएफपी की रिपोर्ट को प्रमुखता से छापा और कहा, इस जीत के बाद मोदी के हाथ मजबूत होंगे, इकॉनमिक विदेश नीति की चुनौतियों का सामना करने के लिए।

लंदन से न्यूयॉर्क और इस्लामाबाद से ढाका तक, प्रकाशनों ने तमिल सुपरस्टार जोसेफ विजय को भी प्रमुख स्थान दिया, जिन्होंने केवल दो साल पहले तमिलगा वेत्रि कज़गम (टीवीके) पार्टी लॉन्च की थी और सत्ताधारी द्रविड़ मुनेत्र कज़गम (डी.एम.के.) पार्टी को परास्त किया।

बीबीसी ने अपने कवरेज में विपक्ष के गढ़ पश्चिम बंगाल पर भाजपा के नियंत्रण पर ध्यान केन्द्रित किया। ''मोदीज़ बी.जे.पी. कॉन्कर्स बंगाल, वन ऑफ इंण्यिा'ज टफैस्ट पोलिटिकल फ्रंटियर्स'' शीर्षक वाले लेख में ब्रिटिश प्रकाशन ने कहा कि पूर्वी राज्य में भाजपा की जीत मोदी के 12 वर्षों के शासन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल होगी।

लेख में कहा गया, ''यह केवल तीन कार्यकाल वाली वर्तमान मुख्यमंत्री की हार नहीं है, बल्कि पार्टी की पूर्वी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कौन होगा प.बंगाल का मुख्यमंत्री

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 मई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के पर्यवेक्षक होंगे और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उनके साथ उप-पर्यवेक्षक होंगे, जबकि मंत्रिमंडल 9 मई को शपथ लेगा।

मुख्यमंत्री पद के लिए कई नाम पहले से ही संभावित उम्मीदवारों में शामिल हैं। सुवेन्दु अधिकारी से लेकर

- शुभेन्दु अधिकारी और दिलीप घोष का नाम चर्चा में है। पर, फैसला अमित शाह के हाथों में है, जिन्हें प.बंगाल में केन्द्रीय पर्यवेक्षक भी बनाया गया है।

वरिष्ठ नेता दिलीप घोष तक – मुख्यमंत्री बनने की दौड़ पूरी तरह खुली है।

भाजपा नेताओं ने कहा है कि पार्टी ने दिलीप घोष के नाम को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है, जो खरगपुर से जीते हैं, साथ ही राज्य इकाई प्रमुख समिक भट्टाचार्य और उपाध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल को भी संभावित मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में माना जा रहा है।

अगर पार्टी महिला मुख्यमंत्री का समर्थन करने का निर्णय लेती है, तो पॉल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मुझे जनादेश से नहीं, साज़िश से हराया गया है'

प.बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनौती दी, केन्द्र सरकार संविधान के प्रावधानों के तहत एक्शन ले सकती हैं

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 मई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आज विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की हार के बाद इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि यह निर्णय जनता का असली मत नहीं, बल्कि एक साज़िश का परिणाम हैं।

उन्होंने टीएमसी की चुनावी लड़ाई को भाजपा के खिलाफ नहीं, बल्कि चुनाव आयोग के खिलाफ बताया, जिसने भाजपा के लिए काम किया। बनर्जी ने मतगणना प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लगभग 100 सीटों पर मत लूटे गए और जानबूझकर गणना धीमी की गई, ताकि उनकी पार्टी का हौसला टूटे।

दृढ़तापूर्वक कहते हुए कि इतिहास का एक काला अध्याय रचा गया है, बनर्जी ने कहा, ''मेरा इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हम जनता

- ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि इस चुनाव के खलनायक है, ज्ञानेश कुमार। उन्होंने जनता के लोकतांत्रिक अधिकार को लूटा है और ईवीएम को लूटा है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि मतदान के बाद भी ईवीएम 80 से 95 प्रतिशत तक कैसे चार्ज थी, यह कैसे संभव है?
- ममता बनर्जी ने कहा, बड़े पैमाने पर उनके पार्टी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया, गिरफ्तार किया गया। यही नहीं पूरे प्रशासनिक अमले को बदल दिया गया, ताकि वे मनमानी कर सकें।
- ममता बनर्जी ने कहा, अब वे सारा ध्यान राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाने पर देंगी।

के मत से नहीं, बल्कि साजिश के कारण हारे। मैं नहीं हारी, मैं लोक भवन नहीं जाऊंगी। वे संविधानिक नियमों के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं।''

कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टीएमसी प्रमुख ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को कमज़ोर करने का आरोप लगाया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जहाँ एसआईआर में सबसे ज्यादा नाम कटे, वहाँ कैसा रहा पार्टियों का प्रदर्शन

प.बंगाल में एसआईआर में वोटर्स का नाम कटना एक बड़ा कारण बताया जा रहा है, भाजपा की जीत का

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 मई। इस साल के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदाताओं का नाम काटा जाना एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया, वही चुनाव, जिसमें भाजपा ने तृणमूल के गढ़ में धावा बोला और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 15 साल के शासन का अंत किया।

- एक रिव्यु के अनुसार, जिन 147 सीटों पर 25,000 से ज्यादा नाम काटे गए, उनमें सबसे ज्यादा सीटें (95) भाजपा को मिलीं और तृणमूल को मात्र 51 सीटें मिलीं।
- 67 सीटों पर 15 से 35 हज़ार वोटर्स के नाम कटे, यहाँ भी भाजपा आगे निकली, उसने 47 सीटें जीतीं और तृणमूल को 19 सीटें मिलीं।
- 62 सीटें ऐसी थी जहाँ 5 से 15 हज़ार नाम कटे थे, यहाँ भाजपा 50 सीटें जीतीं, तुणमूल को 12 सीटें मिली और 13 सीटें ऐसी थीं जहाँ 5 हज़ार व उससे कम नाम कटे थे, वे भी भाजपा ने जीतीं।

चुनाव से ठीक पहले, राज्य के 90 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। यह तब हुआ, जब चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के लिए एसआईआर का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं के रिकॉर्ड को साफ करना था।

तृणमूल ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया लक्षित और पक्षपातपूर्ण थी, और इस बात का डर जताया था कि पार्टी अपना मतदाता आधार खो सकती है। अब जब पार्टी सत्ता खो चुकी है, यह देखने लायक है कि हटाए गए नामों का तालमेल तृणमूल और भाजपा के वोटों के साथ कैसे बैठता है। बंगाल के 147 विधानसभा क्षेत्रों में 25,000 से अधिक नाम हटाए गए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जेपी नड्डा होंगे असम में केन्द्रीय पर्यवेक्षक

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 मई। भारतीय जनता पार्टी ने असम में विधायक दल नेता के चुनाव के लिए केन्द्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केन्द्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा को नियुक्त किया है, जबकि हरियाणा के

- नड्डा के सहायक के रूप में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को नियुक्त किया गया है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सह-पर्यवेक्षक होंगे।

हिमंता बिस्वा सरमा, जिन्होंने 10 मई 2021 को अपने पहले कार्यकाल की शपथ ली थी, अब मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरा कार्यकाल लेने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है, जो व्यापक जीत के बाद केन्द्र-राज्य की मजबूत साझेदारी को दर्शाता है।

'करतारपुरा नाले की चौड़ाई 32.6 मीटर होगी, नाला भी पक्का होगा'

हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, जेडीए ने कोर्ट में शपथ पत्र पेश कर कहा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 5 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के करतारपुरा नाले में अतिक्रमण से जुड़े मामले में दायर जनहित याचिका को जेडीए के जवाब के बाद निस्तारित कर दिया और नाले को मानसून से पहले चौड़ा करने के आदेश दिए। जस्टिस पीएस भाटी और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश राजेन्द्र प्रसाद शर्मा की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए दिए।

जेडीए की ओर से अधिवक्ता अमित कुड़ी ने अदालती आदेश की पालना में शपथ पत्र पेश किया, जिसमें कहा गया कि करतारपुरा नाला, जो कि 4 किमी लम्बा है, इसकी चौड़ाई 32.6 मीटर रखी जाएगी और जल प्रवाह के दोनों ओर पांच-पांच मीटर का कॉरिडोर बनाया जाएगा। परियोजना का डिजाइन एमएनआईटी के विशेषज्ञों के परामर्श से तैयार किया गया है और इसमें आगामी 100 साल की क्षमता का ध्यान भी रखा

- जेडीए ने यह भी कहा, इस नाले के दोनों तरफ 5-5 मीटर का सुरक्षा कॉरिडोर छोड़ा जाएगा।
- जेडीए की ओर से हाई कोर्ट में कहा गया है कि, इस परियोजना का डिज़ाइन एमएनआईटी के विशेषज्ञों के परामर्श से तैयार कराया गया है और इसमें आगामी 100 साल की क्षमता का ध्यान भी रखा गया है।

गया है। जेडीए की ओर से कहा गया कि इस नाले से गाद हटाकर उसे पक्का किया जाएगा। इसके अलावा वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करते हुए इसके सीवरेज को द्रव्यवती नदी के एसटीपी प्लांट से जोड़ा जाएगा।

गौरतलब है कि इस मामले की पिछली सुनवाई में ज़ोन-5 के उपायुक्त ने शपथ पत्र पेश कर कहा था कि करतारपुरा नाले की चौडाई 22 से 30 मीटर कर देंगे और उसके अतिरिक्त 10-10 मीटर का सुरक्षा कॉरिडोर दोनों तरफ छोड़ा जाएगा। उनकी ओर से कहा गया था कि 10 मार्च 2025 को नगरीय विकास विभाग ने जेडीए सचिव को पत्र लिखकर अदालती आदेशों के मुताबिक नाले की चौडाई बढ़ाने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने को कहा था।

भले ही जेडीए ने नाले की चौडाई 30 मीटर के बजाय 32.6 मीटर कर दी है, लेकिन 10-10 मीटर का जो सुरक्षा कॉरिडोर दोनों तरफ छोड़ना था, उसे घटाकर 5-5 मीटर किया है। ऐसे में यह देखना होगा कि हर मानसून में करतारपुरा नाला ओवरफ्लो होने की जो स्थितियां बनती हैं, उनमें कितनी राहत मिलेगी। बताया जा रहा है कि जेडीए के इस नए प्लान के मुताबिक भी करीब 300 स्थायी-अस्थायी अतिक्रमणों को तोड़ा जाएगा। ऐसे में प्रभावित लोग अदालत का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं।

जनहित याचिका में अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश ने बताया कि नाले में जगह-जगह अतिक्रमण हो गया है और नाला पक्का भी नहीं है। अतिक्रमण के कारण कई जगहों पर नाले की चौडाई कम होकर कुछ फीट ही रह गई है। वहीं, उचित व्यवस्था नहीं होने से मानसून में यहां कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। एक युवक कार सहित इसमें बह चुका है। इस दौरान उसकी मौत भी हो गई थी।

गौरतलब है कि पूर्व में जेडीए की ओर से अदालत में रिपोर्ट पेश कर कहा गया था कि नाले की चौडाई तीस मीटर रखने के साथ ही दोनों ओर दस-दस मीटर का कॉरिडोर रखा जाएगा, जिससे कई लोगों के निर्माण इसकी जद में आ गए थे।

'तमिलनाडु में आम कांग्रेस कार्यकर्ता विजय के पक्ष में था'

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 मई। गिरीश चोडणकर, जो तमिलनाडु के लिए कांग्रेस के एआईसीसी इन्चार्ज हैं, ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व का द्रमुक के साथ गठबंधन जारी रखने का निर्णय

- तमिलनाडु में कांग्रेस प्रभारी गिरीश चोडणकर ने कहा कि अगर राहुल गांधी, विजय की पार्टी के साथ गठबंधन करते तो वे 180-190 सीटें जीत सकते थे।

जमीनी स्तर के नेताओं की मजबूत भावना के विपरीत था, कार्यकर्ता अभिनेता विजय की टीवीके (तमिलागा वेत्रि कड़गम) के साथ जाने के पक्ष में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गत लोकसभा में ऐतिहासिक जीत के बाद, गौरव गोगोई जोरहाट में विधानसभा चुनाव क्यों हार गए?

हार का मुख्य कारण था, गौरव गोगोई के बारे में यह चर्चा हो जाना कि वे दिल्ली में संसद में अच्छा काम कर रहे हैं, पर, स्थानीय जनता को समय नहीं दे पाते, संपर्क ढीला पड़ता जा रहा है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 5 मई। असम में एक प्रमुख मुकाबला जोरहाट निर्वाचन क्षेत्र में हुआ, जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार गौरव गोगोई और वरिष्ठ भाजपा नेता हितेन्द्रनाथ गोस्वामी के बीच कड़ी टक्कर रही।

जोरहाट निर्वाचन क्षेत्र ने चौंकाने वाला निर्णय दिया, जिसमें राज्य कांग्रेस प्रमुख को लगभग 22,000 मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा।

इस परिणाम ने व्यापक राजनीतिक बहस को जन्म दिया, क्योंकि गौरव गोगोई कांग्रेस के एक प्रमुख चेहरे और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के पुत्र हैं। यह भी याद रखें कि वे तीन बार सांसद रह चुके हैं।

इस बार, कांग्रेस ने गोगोई के लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में हार का सामना किया, सिवासागर को छोड़कर, जहां सहयोगी पार्टी राइजोर दल के प्रमुख अखिल गोगोई जीते।

गौरव की हार के पीछे कई कारण हैं।

मतदाताओं और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की एक प्रमुख शिकायत यह थी कि गोगोई तक पहुँच पाना संभव नहीं था। कई लोगों ने महसूस किया कि चुनाव अभियान के दौरान वे पर्याप्त रूप से दिखाई नहीं दिए, जिससे उनकी जमीनी संपर्क शक्ति कमजोर हुई। अपने पिता की विरासत और ''अहोम''

- भाजपा ने भी इस सोच को खूब हवा दी कि गोगोई दिल्ली के लिए उपयुक्त हैं। पर, स्थानीय जनता के लिए ''उपलब्ध'' नहीं हैं।
- गोगोई की तुलना में भाजपा के उम्मीदवार हितेन्द्र नाथ गोस्वामी ने बड़ा शांत अभियान चलाया, जिसमें जोशीली भाषणबाजी व धुंआधार वादों का कोई रोल नहीं था। उन्होंने गोगोई की संसद में भूमिका की सराहना की तथा अपने आपको समर्पित स्थानीय नेता के रूप में प्रस्तुत किया।
- इस चित्रण ने स्थानीय वोटर में गोस्वामी के लिए भारी सहानुभूति जगाई, जो उनकी जीत का प्रमुख कारण बनी।

समुदाय से होने की पहचान पर निर्भरता, जो जोरहाट में अच्छी पकड़ रखता है, उलटा असर डालती दिखी।

भाजपा ने सूक्ष्म रूप से एक नैरेटिव चलाया, जिसमें गौरव को राज्य स्तरीय नेतृत्व से ज्यादा, संसदीय राजनीति के लिए उपयुक्त बताया गया, ताकि मतदाता धारणा प्रभावित हो सके।

भाजपा ने चुनाव को लगातार ''विकास'' बनाम ''विपक्षी अड़चन'' के रूप में प्रस्तुत किया। यह नैरेटिव उन मतदाताओं के बीच प्रभावी रहा, जो विकास की धीमी गति को लेकर चिंतित थे।

पिछले पांच वर्षों में जोरहाट में किए गए दिखाई दे रहे विकास कार्यों ने सत्तारुढ़ पार्टी में जनता का विश्वास सुदृढ़ किया और गोस्वामी के लिए अनुकूल माहौल बनाया।

निर्वाचन क्षेत्र के पुन:निर्धारण के बाद इस विधानसभा क्षेत्र में होलोंगापर पंचायत का शामिल होना भी निर्णायक साबित हुआ। पहले यह क्षेत्र पिछड़ा माना जाता था, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें उल्लेखनीय प्रगति हुई, जिसने मतदाता की प्राथमिकता प्रभावित की।

इन सभी कारणों के ऊपर भाजपा का व्यापक प्रचार अभियान था। घर-घर जाकर किये गये प्रचार और स्थानीय नेतृत्व का समन्वित प्रयास नए जुड़े क्षेत्रों में गहरी पहुँच सुनिश्चित करने में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024 में आरपीएससी ने सवाल का जवाब बदला

जयपुर 5 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती- 2024 के एक प्रश्न की गलत जांच करने से जुड़े मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव और आरपीएससी सचिव से जवाब तलब

- हाई कोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव तथा आरपीएससी सचिव से जवाब मांगा।

किया है। इसके साथ ही अदालत ने भूगोल विषय के व्याख्याता पद पर दी जाने वाली नियुक्तियों को याचिका के निर्णय के अधीन रुखा है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने ये आदेश जसवंत सिंह की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि आरपीएससी की ओर भूगोल विषय के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)